

माननीय न्यायमूर्ति K. कन्नन, जे  
गुरचरण सिंह और अन्य, याचिकाकर्ता  
बनाम

सचिवीय शहरी विकास, सरकार  
हरियाणा, चंडीगढ़ और OTHERS, — उत्तरदाताओं

C.W.P. 2008 की संख्या 21758

3 फरवरी, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-अधिग्रहित याचिकाकर्ताओं की भूमि वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन के लिए 'बहिष्कार' के रूप में दावा-सरकार केवल आवासीय भूखंडों के आवंटन को प्रतिबंधित करने वाले निर्देशों को वापस ले रही है केवल नीति परिवर्तन के आधार पर गैर-आवासीय भूखंडों के लिए लाभ वापस लेना-वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन को वापस लेने का निर्णय कमजोर, लंगड़े, असमर्थनीय और मनमाने आधार पर उचित नहीं है याचिका की अनुमति दी गई, उत्तरदाताओं ने भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

माना गया कि अस्वीकृति के लिए लिया गया एकमात्र आधार वर्ष 2003 में नीति में एक कथित परिवर्तन है जो आवंटन को केवल आवासीय भूखंडों तक सीमित करता है। मैंने पहले ही माना है कि इस तरह के प्रतिबंधों का आधार कमजोर, लंगड़ा, असमर्थनीय और मनमाना है। वर्ष 1987 से निर्वासित नीति आवंटन के लिए कोई आर्थिक मानदंड नहीं बताती है। यह निश्चित रूप से प्रासंगिक है, लेकिन अभी तक नीतिगत विचारों में यह आधार नहीं रहा है। राज्य ऐसी नीति का अनुसरण कर सकता है और इसे उन व्यक्तियों तक सीमित कर सकता है जो गरीब हैं और जो विस्थापित हैं, लेकिन निर्वासितों की नीति का विवरण देते हुए अदालत में दायर किए गए दस्तावेज इन दलीलों का समर्थन नहीं करते हैं कि आवंटन के लिए विचार उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें बड़ी मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। (पैरा 11)

डी.एस. चानन, के लिए वकील याचिकाकर्ता

रवि Dun शर्मा, उप महाधिवक्ता, हरियाणा,

सुश्री प्रीति खन्ना, एडवोकेट, के लिए उत्तरदाता 2 और 3.

क. KANNAN; जे.

मैलिस

(1) याचिकाकर्ता, जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने वर्ष 1971 में सरकार की अधिग्रहण कार्यवाही में संपत्ति खो दी थी, वे अभी भी 'निर्वासित' के रूप में वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन पर विचार करने के लिए सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। अपेक्षाएं कुछ नीतिगत विवरणों के आधार पर की गई हैं, जिनके तहत हरियाणा सरकार ने उन व्यक्तियों को आश्वासन दिया था, जिन्होंने अधिग्रहण में संपत्तियों को खो दिया था, जब अधिग्रहण की गई संपत्ति का विकास होता है और आवंटन के माध्यम से वितरण का अभ्यास सफल होता है, तो विशेष आरक्षित मूल्य पर नए आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

(2) याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण 25 जून, 1975 और 15 नवंबर, 1976 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जारी पुरस्कारों के माध्यम से किया गया था। याचिकाकर्ताओं को अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा राशि भी प्राप्त हुई थी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से वर्ष 1987 से विभिन्न समयों पर परिपत्र/निर्देश जारी किए, जिसमें भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को आरक्षित मूल्य पर आवासीय/वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन का आश्वासन दिया गया था। 10 सितंबर, 1987, 9 मई, 1990, 18 मार्च, 1992, 12 मार्च, 1993, 22 अक्टूबर, 1997, 28 अगस्त, 1998, 27 मार्च, 2000, 10 जुलाई, 2002 और 8 दिसंबर, 2003 को दिए गए विभिन्न निर्देश अदालत में दायर किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि चूंकि उनकी पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसलिए वे अपनी आजीविका के एकमात्र साधन से वंचित हो गए थे और आजीविका के स्रोत की बहाली को संभव बनाने वाली सरकार की नीति को अंततः 8 दिसंबर, 2003 के अंतिम निर्देश द्वारा वापस लेने की मांग की गई थी, जब प्राधिकरण ने कहा था कि आवंटन के लिए विचार केवल आवासीय भूखंडों के लिए किया जा सकता है, न कि गैर-आवासीय भूखंडों के लिए। पिछले सभी संचारों में गैर-आवासीय भूखंडों का संदर्भ अनजाने में किया गया था। विज्ञापन जारी किए जाने के समय वाणिज्यिक भूखंड के आवंटन पर विचार करने के अनुरोध को अस्वीकार करने पर, याचिकाकर्ता रिट याचिका के माध्यम से याचिका को खारिज करने वाले पत्र और अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार देने वाली नीति को रद्द करने के लिए आए हैं।

## द्वितीय। परीक्षा कैसे outee नीति विचार थे

### तैयार

(3) इस मुद्दे की जांच करने के लिए कि क्या वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन पर विचार अनजाने में किया गया था, यह मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है कि समय के साथ नीति कैसे विकसित हुई। वर्ष 1987 के बाद से शुरू होने वाले नीतिगत विवरणों में विभिन्न मानदंडों का उल्लेख किया गया है कि आवंटन के दावों को कैसे संबोधित किया जाएगा। पहली बार, जब वर्ष 1987 में पॉलिसी जारी की गई थी, तो यह देखा गया था कि आवंटन केवल तभी किया जाएगा जब भूमि मालिकों के स्वामित्व वाली कुल भूमि का 75% अधिग्रहण किया जाए। ऐसे पात्र उम्मीदवारों में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनके पास 500 वर्ग किलोमीटर तक की जमीन है। यार्ड 100 वर्ग गज की पेशकश की जाएगी और जिन व्यक्तियों के पास 500 वर्ग गज से एक एकड़ से अधिक भूमि होगी, उन्हें 250 वर्ग गज का भूखंड दिया जाएगा और बड़ी भूमि के मालिकों को 350 वर्ग गज के भूखंड दिए जाने चाहिए। यदि किसी विशेष भूमि के लिए कई मालिक थे, तो नीति में कहा गया था कि अधिग्रहण की गई प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए 250 वर्ग गज के एक भूखंड की सीमा के अधीन उन्हें समायोजित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसे आवंटों को इस आशय का एक हलफनामा भी देना चाहिए कि उसकी शहर में कोई दुकान या भूखंड नहीं है। वर्ष 1987 में निर्धारित योजना के आंशिक संशोधन में बाद की योजना 9 मई, 1990 को जारी की गई। इस योजना में फिर से आवंटित की जा सकने वाली भूमि की सीमा और ऐसे आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। योजना में विशेष रूप से कहा गया है कि विस्थापितों को वाणिज्यिक स्थलों के आवंटन के संबंध में, मामले की फिर से जांच की जा रही है और जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा, प्रभावित पक्षों को सूचित किया जाएगा। 1982 में कुछ और संशोधन किए गए, जबकि अभी भी उन व्यक्तियों की पात्रता को बरकरार रखा गया है जो उस श्रेणी तक सीमित हैं, जिन्होंने अपने पास मौजूद कुल भूमि का 75% से अधिक खो दिया था। वर्ष 1993 में बनाई गई नीति में यह कहते हुए और प्रतिबंध लगाए गए हैं कि नीति का लाभ विस्थापितों को नहीं दिया जाएगा, जिनके पास अन्य शहरी संपदाओं में हुडा से आवासीय/वाणिज्यिक भूखंड थे और लाभ स्वयं सह-शेयरों की संख्या के आकार के अनुसार केवल एक भूखंड तक सीमित होगा। 1997-98 के नीतिगत विवरण में आवासीय और गैर-आवासीय दोनों भूखंडों के आवंटन की योजना की परिकल्पना की गई है और कहा गया है कि यदि उसी क्षेत्र में विस्थापितों को भूखंड की पेशकश नहीं की जा सकती है, तो उन्हें शहरी संपदा के अगले आवासीय क्षेत्र में पेश किया जाएगा। वर्ष 2000 की नीति दिनांक 27 मार्च, 2000 को इस न्यायालय के निर्णय की अगली कड़ी के रूप में बनाई गई थी। सुमन अनेजा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य जिनका उल्लेख नीचे

किया गया है। इसने विशेष रूप से निर्धारित किया कि जब भूखंडों को बिक्री के लिए उतारा गया था, तो विस्थापितों के दावे आमंत्रित किए जाएंगे और उन्हें भूखंडों के आवंटन के लिए पूर्व अधिकार होना चाहिए। दिनांक 10 जुलाई, 2002 के नीति विवरण में आपूर्ति से अधिक मांग वाले विस्थापितों की समस्या का समाधान किया गया है और निर्देश दिया गया है कि जब पूर्ण सेक्टरों को जारी किया गया था और विज्ञापन जारी किए गए थे, तो विस्थापितों से विशेष रूप से आवेदन करने और लाभ लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए और विज्ञापन में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि विस्थापितों के दावे को समायोजित करने के बाद, आरक्षण नीति के अनुसार आवंटन के लिए शेष भूखंड उपलब्ध होने चाहिए। यदि निर्वासितों के दावों का निपटान करने के बाद ही अधिशेष होता, तो इस तरह के अधिशेष को सामान्य श्रेणी के तहत पेश किया जाता। नीति विवरण का दिनांक 8 दिसंबर, 2003 का संशोधन अंतिम व्यक्त नीति है जो इसे केवल आवासीय भूखंडों के आवंटन और वाणिज्यिक या औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबंधित करती है। वर्ष 2002 के नीति विवरण में विशेष रूप से कहा गया है कि विज्ञापन जारी होने के समय भी विस्थापितों को सूचित किया जाएगा और सामान्य श्रेणी के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पहले उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा।

**तृतीय। यदि पॉलिसी आवंटन की योजना को मान्यता देती है, तो एक उल्लंघन एक प्रवर्तनीय अधिकार को जन्म देगा।**

(४) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील यह बताएगा कि उन व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने की नीति, जिन्होंने अधिग्रहण की कार्यवाही में संपत्ति खो दी थी और उन्हें निर्वासितों के रूप में चिह्नित किया था, न केवल उन व्यक्तियों के बिगड़े हुए स्वभाव को शांत करने के उच्च उद्देश्य के साथ किया गया था, जिन्होंने संपत्तियों को खो दिया था, बल्कि उन्हें आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए किया गया था, जैसे कि, यदि एक आवासीय कॉलोनी स्थापित करने के लिए एक उत्पादक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाता है, अर्थात् निर्वासित को कम से कम एक आवासीय भूखंड की पेशकश की जानी चाहिए और उसी तरह, यदि अधिग्रहण एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था, तो निर्वासित को एक नए जीवन के समर्थन के लिए कम से कम एक वाणिज्यिक भूखंड की पेशकश की जाएगी। विद्वान वकील के अनुसार, एक उत्पादक भूमि परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पीढ़ियों तक जीवित रहती है, लेकिन खोए हुए संपत्ति के मूल्य के लिए मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से वित्तीय प्रतिदान जल्द ही समाप्त हो जाएगा। विद्वान वकील के अनुसार, एक उत्पादक भूमि परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पीढ़ियों तक जीवित रहती है, लेकिन खोए हुए संपत्ति के मूल्य के लिए मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से वित्तीय प्रतिदान जल्द ही समाप्त हो जाएगा। विद्वान वकील के अनुसार, आवासीय और

गैर-आवासीय दोनों भूखंडों के आवंटन की नीति कुछ निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आवासीय और गैर-आवासीय दोनों भूखंडों को प्राप्त लाभ के संदर्भ में ली गई थी। उनके अनुसार, अनजाने में हुई गलती के आधार पर गैर-आवासीय भूखंडों के लिए लाभ वापस लेना एक लंगड़ा बहाना था। विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए तर्क देते हैं कि राज्य की नीतियों के तहत परिकल्पित आवंटन प्राप्त करने का अधिकार न्यायालय के निर्देशों द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है, जैसा कि अतीत में कई उदाहरणों में किया गया है। इस मुद्दे पर कि निर्वासित व्यक्ति आवंटन के अधिकार के रूप में मांग करने का हकदार है, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ईश्वर सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में सिविल रिट याचिका सं. 1996 का 17506, दिनांक 6 फरवरी, 2002, जहां माननीय न्यायालय आवंटन के मुद्दे पर विचार कर रहा था, राज्य प्राधिकरण द्वारा इनकार किए जाने के बावजूद कि संपत्ति एक औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई थी और निर्वासित नीति के तहत, व्यक्ति केवल एक भूखंड के आवंटन के हकदार होंगे, अगर इसे एक आवासीय कॉलोनी की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया गया था। पीठ ने नीतिगत विवरण को पुनः प्रस्तुत किया लेकिन उसने निम्नानुसार संदर्भ दिया:

*“माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह भी निर्णय लिया है कि उन सभी व्यक्तियों के लिए भूमि आवंटित की जानी चाहिए जिनकी भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की गई थी, यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह कुछ वाणिज्यिक स्थलों को आवंटित/फिर से भेजे। वाणिज्यिक स्थलों/भवनों को नीलामी द्वारा बेचा जाता है और इन परिस्थितियों में, नीलामी होने पर आरक्षित मूल्य पर बाहरी लोगों के लिए आवंटन के लिए स्थलों/भवनों पर विचार किया जा सकता है।” (underline mine)*

उसी का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि दावे को सीमित करने में सरकार का रुख केवल तभी है जब अधिग्रहण आवासीय उद्देश्यों के लिए किया गया था और यह सावित्री देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1) और जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम सम्पूरन सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है (2). सिरिया देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय की खंड पीठ के अभी भी बाद के फैसले में सिविल रिट याचिका सं। 2003 का 17565, दिनांक 6 जुलाई, 2004, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन प्रयोजनों के बावजूद जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, बाहरी लोगों को बाहरी कोटा में आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

गुरु सिंह और अन्य वी. सचिवीय शहरी 421

विकास, हरियाणा का शासन,

(5) (5) इन सभी उपरोक्त निर्णयों में, यह देखा जा सकता है कि अधिग्रहण का उद्देश्य अप्रासंगिक था और सभी दावे आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए थे। न्यायालय औद्योगिक भूखंड या वाणिज्यिक भूखंड के आवंटन के मुद्दे की जांच नहीं कर रहा था। दूसरी ओर, न्यायालय उन स्थितियों से निपट रहे थे जब संपत्ति का अधिग्रहण और विकास वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्देश्य के लिए था, तब भी आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा जब ऐसी आवासीय कॉलोनियों की योजना और विकास किया गया था। धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (3) मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब राज्य द्वारा भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाता है, तो भूमि मालिक बाहरी नीति के संदर्भ में आवंटन के लिए विचार किए जाने के हकदार होते हैं। उपरोक्त सभी निर्णयों में नीति को चुनौती नहीं दी गई थी। अदालतों ने माना कि एक नीति की अवधि के अस्तित्व ने आरक्षित मूल्य पर आवंटन का अधिकार पैदा किया।

(6) उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्रीमती में एक निर्णय पर निर्भर करते हैं। रामो बाई और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (4) यह तर्क देने के लिए कि जब किसी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और मुआवजे का भुगतान किया जाता है, तो निर्वासित/पुनर्वास नीति विशुद्ध रूप से एक कल्याणकारी ओवरचर है और इसे अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय इस नीति के संदर्भ में किया गया था कि प्रति सह-शेयरधारक एक भूखंड को सभी सह-शेयरधारकों के लिए संयुक्त रूप से एक भूखंड में बदल दिया गया था। नीति के तहत घोषित अधिकार के प्रवर्तन की मांग करना एक बात है, लेकिन यह कहना बिल्कुल अलग है कि नीति अच्छी तरह से आधारित नहीं है। उस मामले में, अदालत ने माना कि प्रत्येक सह-मालिक के लिए एक आधार की मांग उचित नहीं थी क्योंकि सरकार ने एक वैध कारण के लिए नीति को बदल दिया था। इस मामले में, स्थिति थोड़ी अलग है। सरकार वर्ष 2002 तक आवासीय और गैर-आवासीय दोनों भूखंडों पर आवंटन की पुलिस जारी कर रही थी और पहली बार, उन्होंने केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए आवंटन पर विचार करने की नीति में बदलाव करने का इरादा किया था और वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन के संबंध में पहले के बयानों को अनजाने में बताया था। प्रत्यर्थी के लिए न्यायोचित वकील अमित बख्शी और दूसरे बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य (5) पर भी निर्भर करता है जब न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी भी निर्वासित को उसी भूखंड में आवंटन का दावा करने का निहित अधिकार नहीं था जिसे अधिग्रहित किया गया था। इस याचिका में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। वह यह माँग नहीं करता कि उसे वही मिले

- 
- (3) 2006 (I) PLJ 249
  - (4) 2007 (3) आरसीआर (सिविल) 711
  - (5) 2006 (3) आरसीआर (सिविल) 685

संपत्ति जो उससे अर्जित की जाती है। चंदर कांता बनाम पंजाब राज्य (6) ने कानून का एक बयान दिया कि विदेशी नीति को किसी भी समय बदला और समाप्त किया जा सकता है। यह निर्णय तब लागू होगा जब आउटसी नीति को ही समाप्त कर दिया गया था। एक अधिकार निश्चित रूप से एक नीति विवरण के माध्यम से बनाया जाता है, लेकिन यहां मुद्दा यह है कि क्या नीति को एक वैध कारण से वापस ले लिया गया है।

IV. नीति में बताए गए वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन का संदर्भ कोई अनजाने में किया गया कार्य नहीं था

(7) केवल आवासीय भूखंडों के लिए आवंटन का प्रतिबंध दिनांक 8 दिसंबर, 2003 के संचार में व्यक्त किया गया है और इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*“उप: हुडा द्वारा स्थापित विभिन्न शहरी संपदाओं में बाहरी लोगों को भूखंडों का आवंटन-इसका स्पष्टीकरण*

*यह इस कार्यालय ज्ञापन सं. ए-आईएल-पी-98/24402-22, दिनांक 28 अगस्त, 1998, उपर्युक्त विषय पर।*

*हुडा द्वारा विकसित विभिन्न शहरी संपदाओं में भूखंडों के आवंटन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आउटसी नीति में संशोधन, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट ज्ञापन/परिपत्र के माध्यम से प्रसारित किया गया है, विशेष रूप से कहता है कि यदि आउटसी नीति के तहत भूखंड की पेशकश उसी क्षेत्र ("गैर-आवासीय" के रूप में विकसित) में आउटसी को नहीं की जा सकती है, तो उन्हें शहरी संपदाओं के अगले आवासीय क्षेत्र में केवल एक आवासीय भूखंड की पेशकश की जाएगी, जिसे हुडा द्वारा जारी और विकसित किया जा सकता है। अर्थात्, वह भूमि स्वामी जिसकी भूमि किसी क्षेत्र के विकास के लिए अधिग्रहित की गई है, निर्धारित पात्रता/पात्रता मानदंडों के अनुसार केवल आवासीय भूखंड का हकदार होगा। ऊपर निर्दिष्ट 28 अगस्त, 1998 के परिपत्र में जहां कहीं भी 'वाणिज्यिक' शब्द का उल्लेख किया गया है, उसे अनजाने में वापस लिया गया माना जा सकता है।”*

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वाणिज्यिक आवंटन उपलब्ध कराने का विकल्प कभी भी अनजाने में लिया गया निर्णय नहीं हो सकता था। इस तरह की लापरवाही इतने लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती थी और इसे छोड़ा नहीं जा सकता था

(६) १ ९९ ६ (१) आरआरआर ३ R४



यह तब भी देखा गया जब वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक योजना प्रस्तुत कर रहे थे। यदि वर्ष 2003 में उनके पास केवल आवासीय भूखंडों के आवंटन द्वारा पुनर्वास के बारे में सोचने के लिए अलग-अलग नीतिगत विचार थे और आरक्षित मूल्य पर एक वाणिज्यिक या औद्योगिक भूखंड की पेशकश नहीं की गई थी और इस तरह का नीतिगत विचार तर्कसंगत आधार पर किया गया था, तो भी कोई कानूनी आपत्ति नहीं हो सकती थी। यह हमेशा कार्यपालिका ही होती है जो नीति तैयार करती है और उसे लागू करती है। अदालतें आम तौर पर नीति के कार्यकारी मामलों को निर्देशित नहीं करती हैं। न्यायिक कार्य कानून के दायरे में यह जांचने के लिए होगा कि क्या कोई विशेष नीति उचित है या नहीं, क्या यह समानता, गैर-भेदभावपूर्ण चरित्र, मनमानेपन की कमी आदि की संवैधानिक गारंटी की कसौटी पर खरी उतरती है। या क्या अधिकार का स्रोत ठोस कानूनी आधार पर निर्धारित किया गया है। दिलासिंह बनाम पंजाब राज्य (7) में इस न्यायालय ने किसी राज्य को किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी नीति बदलने की प्राथमिकता दी। ऐसे मामले में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं होता है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता अपने दावे को रोक के सिद्धांत पर आधारित नहीं कर रहा है। दूसरी ओर, उनकी आपत्ति यह है कि बाहरी नीति के लागू होने का प्रतिबंध केवल आवासीय भूखंडों पर था और गैर-आवासीय भूखंडों या वाणिज्यिक भूखंडों को छोड़कर, इसे मनमाने ढंग से चुनौती दी गई है क्योंकि नीतिगत निर्णय में यह नहीं बताया गया है कि परिवर्तन वर्ष 1987 से कैसे आया है जब इसे आवासीय और वाणिज्यिक दोनों भूखंडों के लिए विस्तारित किया गया था और अनजाने में त्रुटि की अभिव्यक्ति के अलावा कोई निश्चित विवरण सामने नहीं आया था, सरकार के लिए किसी भी वाणिज्यिक भूखंड की पेशकश से पीछे हटना आवश्यक हो गया था। मनमानेपन को विवादित पत्र में व्यक्त किए गए तरीके से लिखा जाता है। वर्ष 1983 से शुरू होने वाले नीति विवरणों में से प्रत्येक में की गई अभिव्यक्ति की सुसंगत रेखा, नीति को वाणिज्यिक के साथ-साथ आवासीय भूखंडों दोनों के लिए लागू करती है, अनजाने में त्रुटि के तुच्छ विचार पर रातोंरात नहीं बदल सकती है। 2003 में लिया गया निर्णय उतना ही सनकी है जितना कि एक बयान कि उसने पनीर को चाक समझ लिया था। 2003 के विवादित संचार में कहीं भी ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि वाणिज्यिक भूखंडों को बाहर करने का कोई सचेत निर्णय लिया गया था। असावधानी के असमर्थनीय आधार पर योजना की आकस्मिक वापसी होती है। मानवीय त्रुटियाँ एक लापरवाह गलती को स्वीकार करती हैं, लेकिन अदालत में प्रस्तुत की गई नीति एक सचेत निर्णय का परिणाम होनी चाहिए थी। यह एक बेपरवाह दृष्टिकोण नहीं हो सकता था और यदि यह कभी था, तो यह अपमानजनक और सख्त न्यायिक चेतावनी के लिए उत्तरदायी है, जो कि जिस प्रकृति

424ILR. पंजाब और हरियाणा 2010 (2)  
में न्यायिक हस्तक्षेप किए जाते हैं, उसे विवेक के उपयोग की कमी के कारण रद्द कर दिया जाएगा।

### **क्या याचि क्या याचिकाकर्ताओं ने लापरवाही की है?**

(8) राज्य अधिकारियों द्वारा बचाव में तर्क यह था कि वर्ष 1976 में अधिग्रहित की गई संपत्ति के लिए, रिट याचिका घटना के 32 वर्ष से अधिक समय बाद वर्ष 2008 में दायर की गई थी और इसलिए रिट याचिका को खंडों द्वारा वर्जित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि कार्रवाई का कारण केवल तभी उत्पन्न होगा जब अर्जित की गई संपत्ति को आवंटन के लिए उपयुक्त बनाया जाए और जनता को बिक्री के लिए पेश किया जाए। संपत्तियों को केवल वर्ष 2005 में नीलामी द्वारा बिक्री के माध्यम से पेश किया गया था और इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा आवंटन की मांग की गई थी। इस स्थिति के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्रीमती को संदर्भित करते हैं। सुमन अनेजा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (8) जहां इस न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वासितों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सुसंगत तिथि वह तिथि होगी जिस पर विकास के बाद चित्रित क्षेत्रों को बिक्री के लिए जारी किया जाएगा।

(9) यह भी प्रतिवाद किया जाता है कि वर्ष 2002-2003 के बीच, नीति में परिवर्तन किया गया था और याचिकाकर्ताओं ने 2002 में ही योजना के तहत आवेदन नहीं किया था और उन्होंने नीति में परिवर्तन के बाद ही आवेदन किया था। इस विवाद को दो आधारों पर खारिज किया जाना चाहिए: एक, आवंटन के लिए आवेदन करने वाले बाहरी व्यक्ति से अधिक, प्राधिकरण स्वयं इसे जनता के लिए नीलामी में रखने से पहले आरक्षित मूल्य पर एक बाहरी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। हुडा की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने श्रीमती के निर्णय पर भरोसा किया। भगवंती बनाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (9) का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करने के लिए अधिकारियों से अनिश्चित काल के लिए अपेक्षा नहीं की जाती है। उपरोक्त मामले में, यह न्यायालय उन व्यक्तियों के दावों पर विचार कर रहा था, जिन्होंने नीति में बताए गए निर्धारित समय से परे अपने आवेदन किए थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राधिकरण से अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह अपनी सुविधा के अनुसार आवेदन करने के लिए चार वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करे। अस्वीकृति उसी आधार पर की गई

थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि याचिकाकर्ता आवेदन के लिए निर्धारित किसी विशेष अवधि का उल्लंघन नहीं कर रहा था। दूसरी ओर, उन्होंने नीलामी की तारीख से पहले आवेदन किया था। इसलिए निर्णय लागू नहीं हो सकता है। इस मामले में, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता विभिन्न आवेदनों के माध्यम से इन सभी वर्षों से आवंटन के लिए दावा कर रहे हैं। इस संपत्ति को 10 अक्टूबर, 2005 को 'अमर उजाला' में एक विज्ञापन के माध्यम से नीलामी के लिए रखा गया था और याचिकाकर्ताओं ने 5 अक्टूबर को आवेदन प्रस्तुत किया था

2005 और डायरी नं। 19126 और 19125, दिनांक 5 अक्टूबर, 2005। याचिकाकर्ताओं ने एक सिविल रिट याचिका नं. 2005 का 17265, जिसे इस न्यायालय द्वारा आवेदन को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दिया गया था। यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट, जिसका अर्थ है कि न्यायालय का एक कार्य कोई नुकसान नहीं कर सकता है। यदि एक स्तर पर, न्यायालय ने पाया कि आवेदन अपरिपक्व था, तो अगले दौर में जब याचिका दायर की जाती है, तो बचाव पक्ष को यह नहीं लिया जा सकता है कि इसमें देरी हुई थी। दो, याचिकाकर्ताओं के तर्क को अस्वीकार करने का राज्य का प्रयास इस तथ्य से भी बुरा होगा कि केवल आवासीय भूखंडों के लिए आवंटन की अनुमति देने का प्रतिबंध उस प्रभाव के लिए किसी भी सचेत नीतिगत निर्णय द्वारा समर्थित नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन को वापस लेने का निर्णय किसी भी उचित नीति के आधार पर नहीं लिया गया था। इसे वापस लेने का कारण, मैंने पहले ही असमर्थनीय माना है।

(10) इस मामले में, याचिकाकर्ताओं को विचार के लिए पात्रता इस आधार पर दी गई है कि नीति वाणिज्यिक भूखंडों के लिए लाभप्रद नहीं है और दावा देर से किया गया है। अस्वीकृति के दोनों आधार, हम पहले से ही असमर्थनीय देख चुके हैं। सावित्री देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (10) में कहा गया है कि केवल भूमि का गैर-उपयोग बाहरी लोगों को संपत्ति को अधिग्रहण से मुक्त करने के लिए सरकार से अनुरोध करने का अधिकार नहीं देता है। आवंटन की मांग करने का अधिकार केवल तभी उपलब्ध होगा जब संबंधित योजना या नियम हों। यह निर्णय उस तर्क की रेखा से अलग नहीं है जिसे हमने यह निष्कर्ष निकालने में अपनाया है कि याचिकाकर्ता आवंटन के लिए विचार करने का हकदार है

## VI. याचिकाकर्ता जिन्हें बड़ा मुआवजा मिला है, नहीं

oustees ?

(11) प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं ने 3 करोड़ से अधिक का भारी मुआवजा प्राप्त किया है और निर्वासित नीति स्वयं उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है, जो हाशिए पर हैं और जिन्हें अधिग्रहण से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बयानबाजी में यह विवाद एक राजनीतिक बयान के समान है लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। यह याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करने वाली विवादित कार्यवाही में उल्लिखित आधार भी नहीं है। अस्वीकृति के लिए लिया गया एकमात्र आधार वर्ष 2003 में नीति में एक कथित परिवर्तन है जो केवल

(१०) १ ९९ ६ (३) आर.सी.आर. (सिविल) 199

आवासीय भूखंडों के आवंटन को प्रतिबंधित करता है। मैंने पहले ही माना है कि इस तरह के प्रतिबंध का आधार कमजोर, लंगड़ा है, असमर्थनीय और मनमाना। वर्ष 1987 की आउटसी नीति में आवंटन के लिए कोई आर्थिक मानदंड नहीं दिया गया है। यह निश्चित रूप से प्रासंगिक है, लेकिन अभी तक नीतिगत विचारों में यह आधार नहीं रहा है। राज्य ऐसी नीति का अनुसरण कर सकता है और इसे उन व्यक्तियों तक सीमित कर सकता है जो गरीब हैं और जो विस्थापित हैं, लेकिन अदालत में दायर किए गए दस्तावेजों में बाहरी लोगों की नीति का विवरण इस याचिका का समर्थन नहीं करते हैं कि आवंटन के लिए विचार उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें बड़ी मुआवजा राशि प्राप्त हुई है।

### सातवीं. निष्कर्ष

(12) याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रत्यर्थियों को भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है और भूखंडों का आकार और संख्या याचिकाकर्ताओं को 2003 की आक्षेपित कार्यवाहियों द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, जो इस रिट याचिका द्वारा खारिज कर दिया गया है, प्राप्त नीति सीमा के आधार पर आवंटित की जाएगी। रिट याचिका की अनुमति रुपये की अनुमानित लागत के साथ दी गई है। 10,000।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य सैनी  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
रेवाड़ी (हरियाणा)

मुकुल इलुडगल से पहले, सी. जे. एंड. जसबीर सिंह, आईएल  
सुद रानी और OTHERS — याचिकाकर्ता  
बनाम

पंजाब की स्थिति और OTHERS — उत्तरदाताओं  
2008 के C.W.P नंबर 6801 और &  
कनेक्ट किए गए WRIT PETITIONS

20 अप्रैल 2010

भारत का संविधान, 1950 — Arts. 14, 16, 38 (2) और 226 -  
शैक्षिक सेवा प्रदाताओं के पदों की भर्ती— राज्य जिन उम्मीदवारों के पास  
5 अंकों का भार है, उन्हें सरकार प्रदान करती है ग्रामीण स्कूलों से उनकी  
मध्य और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की गई— अध्ययन के आधार पर ग्रामीण  
भार का समर्थन करने वाली सरकार पंजाबी विश्वविद्यालय द्वारा गंभीर  
नुकसान का प्रदर्शन किया गया ग्रामीण छात्रों द्वारा उनकी भौगोलिक  
स्थिति के आधार पर और सिद्धांतों के समान अवसर से वंचित करना—  
एक ग्रामीण के लिए वजन असमानता को बढ़ावा देने से दूर के उम्मीदवार,  
बहाल करने के लिए प्रयास करते हैं इस प्रकार, असमानताओं के बीच  
समानता, अनुच्छेद 14 के जनादेश को पूरा करती है संविधान— हालांकि,  
इस तरह के भार एक उचित पर आधारित है, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय  
— याचिकाओं द्वारा उद्देश्य और डेटा आधारित अध्ययन खारिज कर दिया.